SHRI ASOKE KUMAR SEN: Sir, let me be categorical in saying that everybody's opinion will be respected and taken into account.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार जब यह जानती है कि समान नागरिक संहिता नहीं बन सकती इसलिए कि मुस्लिम कम्यूनिटी इस को टूथ एंड नेल पहले से ही विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है और एक समय उन्होंने किया भी है एक बार नहीं अनेक बार इसका प्रत्यक्षीकरण भी हुआ है। और तो और मंत्रिमंडल के सदस्यों में से किसी ने एक वक्त और किसी ने दूसरे वक्त बोल कर विरोध किया है। यहां तक कि एक मंत्री ने तो पद भी खोया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे कादरशाह जी ने कहा कि अगर सरकार का फंडामेंटलिज्म के खिलाफ और धर्म निरपेक्षता की नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करने का यदि संकल्प हो तब तो इस पर बात छेड़ें और अगर संकल्प सरकार का नहीं है और फंडामेंटेलिज्म से नहीं लड़ सकते धर्म निरपेक्षता का निवारण नहीं कर सकते तो बात छेड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है सरकार दूसरे लोगों को धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाने के लिए सिर्फ इस बात को उठाती है। कुछ करने का कोई संकल्प या कोई दृढ़ता दिखाने का कहीं पर भी सरकार ने कोई कदम नही उठाया क्या सरकार ऐसा कोई कदम बता सकती है।

श्री एच०आर० भारद्वाज : माननीय सदस्य का आरोप बिल्कुल निरर्थक है। जहां तक फंडामेंटलिस्ट्स ऐलीमेंट से लड़ने का सवाल है सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है और समय-समय पर वेरियस इश्यूज पर सरकार का दृष्टिकोण हाऊस में आ चुका है। अब कुछ आदमी, कुछ माइनोरिटीज किस इशू पर किस बात पर साथ देते हैं या यूनिफार्म कामन सिविल कोड लाने में, जब तक हम इसे जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इसको बंद कर दें तो बंद करने से जो कंस्टीट्यूशन में नेशनल आब्जेक्टिव्स हैं वे पूरे नहीं होते डायलाग से अगर कोई बात बनती है और उसमें ओपन माइन्ड से डायलाग होता है तो उसको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार पर आरोप लगाकर आप अपनी रिस्पोंसिबिलटी से मुक्त नहीं हो सकते। हर आदमी जो इस सदन में बैठा है चाहे वह किसी पार्टी से हो उसको अपने विचार रखने की आजादी है। दूसरी कम्युनल पार्टीज भी हैं। वे लोग चाहते हैं कि यह मसला तय न हों। हर आदमी का फज होता है कि अपना दृष्टिकोण रखे। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का अपना दृष्टिकोण क्या है (**व्यवधान**)

New model cars by Maruti Udyog Limited

*163. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:†
SHRI RASHEED MASOOD:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Maruti Udyog Limited propose to manufacture two new models of cars;

(b) if so, what are the details thereof stating the nature and extent of foreign collaboration, if any, in the venture; and

(c) what is its likely imapct on the indigenition programme of Maruti and on the ancillary manufacturers with the level of imports remaining high with the introduction of new models of cars?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (PROF. K. K. TEWARY): (a) and (b) Maruti Udyog Limited have submitted a proposal to Government for manufacturing a three box car with two options of engine, viz. 1000/1300 cc within their existing collaboration agreement with M/s. Suzuki Motor Co., Japan.

(c) It is proposed to utilise the existing net-work of Maruti's vendors to

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Satya Prakash Malaviya.

achieve indigenisation level of 75 per cent in the first year going upto 95 per cent in the third year of production of proposed models.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के (क और (ख) में यह बताया है कि मारूति उद्योग ने दो विकल्प तीन खानों वाली कार का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मारूति उद्योग ने जब यह प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है तो उस प्रस्ताव का विस्तृत विवरण क्या है और उसको स्वीकार करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

प्रो० के०के० तिवारी : सभापति महोदय, सन् 1986 में यह प्रपोजल सरकार को मारूति उद्योग ने सबमिट किया और जैसा कि माननीय सदस्य जानते है, तीन बक्स वाली कार मारूति 800 से थोड़ी बड़ी होगी । इसमें तीन खाने होंगे । एक इंजिन का खाना होगा, एक पैसेंजर्स का खाना होगा और एक सामने रखने का खाना होगा । यह तीन बक्स वाली कार का प्रापोजल सरकार के सामने है और सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मारूति उद्योग ने जब से यह कार बनाने का काम शुरू किया है तब से मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने और कौन-कौन सी गाड़ियों के माडल मारूति उद्योग ने बंद किये है और वे कब से किये है और उनके बंद करने के क्या कारण है ?

प्रो० के०के० तिवारी : मारूति उद्योग में तीन माडल की गाड़ियां बनती रही है—पहली मारूति कार, दूसरी जीप और तीसरी वैन । वैन दो प्रकार की है । एक फलेट रूफ की वैन और दूसरी हाई रूफ वैन । इन गाड़ियों में कोई भी माडल बन्द नहीं किया गया है । पहली कार के माडल में इम्प्रूवमेन्ट करके दूसरा माडल इंट्रोड्यूस किया गया है । जीप और वैन दोनों का उत्पादन हो रहा है । किसी माडल को बन्द नहीं किया गया है ।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Mr. Chairman, Sir, would the hon. Minister kindly tell us in which way these two new, proposed car would be better than the other cars which are on the market and what price range he is going to think of when they arrive on the road for people and whether it will be more full-efficient than the present cars?

PROF. K. K. TEWARY: Mr. Chairman, Sir, the taste of the pudding lies in the eating. The Maruti car that has been introduced in the market has shown that there has been a quantum jump in technology, in quality, service. So, any model introduced by Maruti, it goes without saying, will be a model of excellence as we have established by the earlier models.

DR. BAPU KALDATE: He must not be having the pudding. How can he have the taste?

PROF. K. K. TEWARY: Therefore, we feel that the new model of car that we are proposing to introduce, the proposal for which is pending with the Government, once it is in the market, will be much better in the sense of high level of its technology, fuel efficiency and other services.

About pricing, I think, Sir, the proposal is yet under the consideration of the Government. The cost cannot be worked out at this stage.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Sir, in the proposal made by the Maruti Udyog Limited they must have given the price.

MR. CHAIRMAN: No, it cannot be. The Minister is right in saying that the exact price will be worked out at that stage.

श्री रजनी जन साहू : सभापति महोदय, मारूति कार सौ सी सी की हो या तेरह सौ सी सी की बनें, बड़ी बने या छोटी बने, यह सांसदों की प्रायरिटी पर मिलने वाली नहीं है । इसकी कीमतें रोज बढ़ती जा रही है । तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो आने वाला कोलोबरेशन है उस में एलीमेंन्ट आफ फारेन एक्सचेंज क्या इन्वाल्व है और कब तक हम पूर्ण रूप से अपनी टैक्नालाजी पर, विदेशी टैक्नालोजी पर आधारित नही, बल्कि अपनी टैक्नालाजी के आधार पर इनको बना सकेंगे ?

प्रो० के०के० तिवारी : सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य ने दो प्रश्न किये है । पहला प्रश्न उनका है कि सांसदों को यह कार प्रायरिटीज के आधार पर मिलेगी कि नहीं तो सभापति महोदय, जैसा कि आपको मालम है, सदन को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ गाइड लाइंस तय कर दी है और उसके हिसाब से ही कारों का एलाटमेंट होता है और जो मैनुफैक्चर कोटा है उसमें संसद सदस्यों की कैटेगरी नहीं है । लेकिन हम लोगों ने मारूति उद्योग की तरफ से रिवीजन पेटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें हम लोगों ने सुझाव दिया है कि संसद सदस्यों की भी एक कैटेगरी हो जैसें कि पत्रकार है या विशिष्ट समाजसेवी है, ऐसे व्यक्तियों की भी सूचिका होनी चाहिए । (व्यवधान).....

सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न जो फारेन एक्सचेंज के संबंध में है इसमें फारेन एक्सचेंज कम्पोनेन्ट क्या होगा, इसके बारे में मैं सूचना देना चाहूंगा कि नया माडल, जो नया प्रोजेक्ट हमारा है उसका पूरा खर्चा 122 करोड़ रूपया है और इस 122 करोड़ रूपये में दो इंजन की बात है तो पहला इंजन जो हजार सी सी का है वह हमारी जिप्सी का इंजन है उस पर 1 हजार सी सी की कार बनेगी और दूसरा माडल जो 13 सौ सी सी का है उस पर अनुमानित खर्चा 50 करोड रूपया है और टोटल फारेन एक्सचेंज जो खर्च होगा वह $50 मिलियन है । मारूति का प्रपोजल है यह फारेन एक्सचेंज हम इन्टरनेशनल मार्केट में रेज करेंगे और दूसरी सूजूकी इसकी जो इक्विटी है उसको इन्हांस करके हम फारेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेन्ट को मीट करेंगे और जो और रूपया कम्पोनेन्ट का है वह इन्टरनल रिसोंर्सेज को जनरेट करके हम करेंगे ।

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन जितनी तेजी से माडल बदल रहे है उससे यह बात सही साबित होती है कि हिन्दुस्तान के लोगों ने बहुत सी कारों मे सफर करके बहुत नुकसान उठाया है । लेकिन जितनी तेजी से माडल बदल रहे है, मारूति उद्योग के, इससे एक कंज्यूमर संस्कृति देश में फैलने की ज्यादा संभावना है क्योंकि बड़ी कारें होंगी, बड़े लोगों की दौड़े बढेगी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो कार पहले बनाई है उसको अबेंडन करके 6 महीने साल भर में दूसरी ले आये और जो आप की कारे है वे बिक नहीं रही है, जिप्सी गाड़ी बिक नहीं रही है और वैन बिक नहीं रहे है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नये दो माडल जो आयेंगे तो उसके बाद जो आपके फिलहाल चलने वाले माडल है उनको आप अबेंडन करेंगे या चालू रखेंगे ? इस संबंध में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई सर्वे की योजना आपने बनाई है जिससे पता चले कि इन परिस्थितियों में इन माडल्स का क्या हश्र होगा ?

दूसरा, श्रीमन् जिन लोगों के पास इस वक्त जिप्सी या दूसरे वैन है ो इसमें खतरा यह होगा कि आपका सारा ध्यान नये माडलों की ओर चला जायेगा और इन गाड़ियों के जो स्पेयर पार्टस है' वे आज भी हमको नहीं मिलते है और उस सूरत में और भी मिलने की संभावना नहीं है । तो इस संबंध में क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे क्या आप इन स्पेयर पार्टस को बनाते रहेंगे ताकि उनकी री–सेल वेल्यू खत्म न हो जाय और कंज्यूमर सफर न करें ?

प्रो० के० के० तिवारी : सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य की संभावनायें जो है, शंकायें जो है, आशंकायें जो है वे निराधार है । जो माडल हमने इन्ट्रोडयूज किया है वह माडल हमने इम्प्रूव किया है और उसको इम्प्रूव करने के बाद जो पहले के माडल थे उनके स्पेयर पाटस भी हम बनाते है और हम हमेशा यह कोशिश करते है कि स्पेयर पार्टस जो है उनकी कास्ट ठीक हो, उसकी कास्ट हमेशा हमारे ध्यान में रहती है । जहां तक संस्कृति की बात इन्होंने कही, कंज्यूमर कल्चर की बात की, उसके संबध में कहना है कि मारूति के नये माडल माकट में आ जाय तो उससे हम कोई यह नहीं समझते है कि इससे कोई गिरावट आयेगी । यह संस्कृति टैक्नालाजी की है और वह बेहतर टक्नालाजी होगी और इससे कस्टमर को ज्यादा सन्तोष होगा, जो वह पैसा खर्च करेगा उसका फायदा मिलेगा ।

SHRI G. SWAMINATHAN: Mr, Chairman, Sir, as Maruti car users, we are very happy with the existing technology itself. The purpose for which Maruti car is purchased is that it will be an economical car for the middle-class people. Recently the price of car has gone up by Rs. 10,000 and the middle-class people are finding it difficult to purchase it. Recently we had been to the Udyog Bhavan and we were informed that they were not making much profit on the Maruti cars, but they are making profits on the deluxe cars and they are expected to make more profits on the two new model cars. Ultimately the company wants to make better profits on new model cars. Therefore, I want to know whether the Government will retain at least one model which will be cost effective for the middle-class people.

Another thing, spare parts are not available even now. It has become rare and after the recent levy the price of spare parts has gone up by 25 per cent. I would like to know from the Minister, what steps the Government has taken to make spare parts available to the people who purchased Maruti cars earlier.

PROF. K. K. TEWARY: Sir, although it is a suggestion for action, but I take this opportunity to assure the Member and the House that we are keeping constant watch on the prices. It is for this reaction the process of indigenisation has not been of the order that was expected, because we have stringent parameters for costs and quality. Even now all the spare parts, whether indigenous or imported, they are available in plenty and at reasonable costs. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: If you want spare parts, you apply to the Minister. He says that they are available in plenty.

SHRI KAPIL VERMA: Sir, the new budget has imposed some levy and has increased the taxes. As a result of this, Maruti car price has also been affected. May I know from the Minister how does it affect the price of two new model cars which he is going to manufacture and in what manner the price of the existing car called Maruti 800 will be aeffcted? What was the original price of this small car and what is the present price?

MR. CHAIRMAN: They have started repeating the question. Have your any answer?

PROF. K. K. TEWARY: Sir, I have already replied to this question.

MR. CHAIRMAN: Next question.

CBI case against ONGC officers

*164. SHRI KAPIL VERMA: †

SHRI J. P. GOYAL:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the CBI has registered a case against two general managers and a deputy manager of the ONGC for allegedly misleading higher officials and causing a loss of about Rs. 59 lakhs to the Commission; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma.